लैंको अनपरा पावर लिमिटेड

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 6223/2016)

18 अक्टूबर, 2016

[ए. के. सिकरी और एन. वी. रमना, जे. जे.]

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996- भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996- अपीलकर्ताः निर्माण गतिविधि शुरू करना जिसमें उन्होंने अपने कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई थी- सिविल कार्यों के निर्माण की प्रक्रिया में, निर्माण श्रमिकों को शामिल किया गया- प्रतिवादी अधिकारियों का मामला कि अपीलकर्ता बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधान लागू होने के बाद से निर्माण कार्य में लगे उक्त श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर का भुगतान करें- अपीलकर्ताओं का मामला कि कारखाने अधिनियम के प्रावधान अपीलकर्ताओं के भवन/परियोजना के निर्माण पर लागू होते हैं- आयोजित किया गयाः निर्माण श्रमिक कारखाना अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं- इस प्रकार, वे बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के तहत ऐसे श्रमिकों के लिए प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों के हकदार हैं- अपीलकर्ता उक्त श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर का भुगतान करने के हकदार हैं- कारखाना अधिनियम, 1948

अपीलों और याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 निर्माण श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में नहीं आते हैं और

इसलिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत ऐसे श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों से इनकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 34] [759- एफ- जी]

1.2 कारखाना अधिनियम की खंड 2 (एम), 2 (के) और 2 (1) के संयुक्त पठन पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि "कारखाना" वह प्रतिष्ठान है जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया बिजली की सहायता के साथ या उसके बिना की जाती है। इस प्रकार इस विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण गतिविधि को जारी रखना एक पूर्व शर्त है। यह ध्यान दें भी उतना ही उचित है कि इसमें केवल वे श्रमिक शामिल हैं जो उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जहाँ तक इन अपीलार्थियों का संबंध है, भवन का निर्माण उनकी व्यावसायिक गतिविधि या निर्माण प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में, भवन का निर्माण विशेष विनिर्माण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जो इनमें से अधिकांश अपीलों में बिजली का उत्पादन, संचरण और वितरण है। जाहिर है, जो श्रमिक भवन के निर्माण में लगे हुए हैं, वे भी कारखाने अधिनियम के तहत 'श्रमिक' की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। इन दोनों पहलुओं पर कोई दरार नहीं है और दोनों पक्ष समान स्थिति में हैं। इसके बाद यह है कि ये निर्माण श्रमिक कारखाने अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते हैं। [पैरा 21] [753- डी- जी]

1.3 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि अपीलार्थियों का निवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो अपीलार्थियों द्वारा शुरू किए गए भवन के निर्माण में लगे निर्माण श्रमिक, जिनका अंततः कारखाने के रूप में उपयोग किया जाना है, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधानों से भी बाहर रहेंगे। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) में 'भवन और अन्य निर्माण कार्य' की परिभाषा प्रदान करते समय यह इरादा नहीं हो सकता है। [पैरा 22) [753- जी- एच; 754- ए]

1.4 उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं ने कारखाने में काम करने के लिए पंजीकरण के लिए कारखाने अधिनियम की खंड 6 के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है, इसलिए यह नहीं होगा कि वे कारखाने अधिनियम के अर्थ के भीतर "कारखाने" के विवरण का जवाब दें। कारखाना की परिभाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस चरण से पहले, जब परियोजना का निर्माण पूरा हो जाता है और निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कारखाना अधिनियम की खंड 2 (एम) के अर्थ में 'कारखाना' अस्तित्व में नहीं आता है ताकि वह उक्त अधिनियम के दायरे में आए। [पैरा 23] [754- बी- सी]

1.5 बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) तीन भागों में है जो भवन या निर्माण कार्य से संबंधित है। पहले भाग में, विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उक्त अभिव्यक्ति में शामिल किया जाना है, अर्थात्, निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस। परिभाषा का दूसरा भाग उन इमारतों या कार्यों के लिए है जिनके संबंध में उपरोक्त गतिविधियाँ की जाती हैं। परिभाषा के तीसरे भाग में यह निर्धारित करते हुए बहिष्करण खंड शामिल है कि इसमें 'कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य शामिल नहीं है जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 या खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं'। इस प्रकार, परिभाषा के पहले भाग में गतिविधि की प्रकृति शामिल है; दूसरे भाग में वह विषय वस्तु शामिल है जिसके संबंध में गतिविधि की जाती है और तीसरे भाग में उन भवनों या अन्य निर्माण कार्यों को शामिल नहीं किया गया है जिन पर कारखाने अधिनियम या खान अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। [पैरा 24] [754- डी- एफ]

1.6 अपीलार्थियों की परियोजनाओं का निर्माण "भवन या अन्य निर्माण कार्य" की परिभाषा के अंतर्गत आता है क्योंकि यह परिभाषा के पहले दो तत्वों को संतुष्ट करता है। यह देखने के लिए कि क्या अपवर्जन आदेश लागू होता है, 'लेकिन इसमें कोई

भवन या अन्य निर्माण कार्य शामिल नहीं है, जिसके लिए कारखाना अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। कारखाना अधिनियम के प्रावधान अपीलार्थियों के भवन/परियोजना के निर्माण पर लागू नहीं होते हैं। कारखाना अधिनियम के प्रावधान केवल तभी "लागू" होंगे जब विनिर्माण प्रक्रिया शुरू होगी जिसके लिए भवन/परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और परियोजना के निर्माण की गतिविधि पर नहीं। इस प्रकार अपवर्जन खंड की व्याख्या की जानी चाहिए और यह उक्त खंड का स्पष्ट अर्थ होगा। [पैरा 25] [754- जी- एच; 755- ए- बी]

ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ 1980 (1) एससीआर 61:(1979) 4 एस. सी. सी. 573- संदर्भित।

1.7 परिभाषा के अपवर्जन खंड के लिए जिम्मेदार उक्त अर्थ भी उस उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप है जिसे बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के अधिनियमन द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यदि अपीलार्थियों द्वारा सुझाए गए इस प्रावधान के निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो भवनों/परियोजनाओं के निर्माण में लगे निर्माण श्रमिकों को न तो कारखाना अधिनियम का लाभ मिलेगा और न ही बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम/कल्याण उपकर अधिनियम का। विधायिका की यह मंशा नहीं हो सकती थी। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम निर्माण श्रमिकों को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून के टुकड़े हैं। [पैरा 26] [755- एफ- एच]

1.8 एक सामाजिक सुधार कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एक अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो।' . ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम में निहित 'श्रेष्ठ उद्देश्य' को तब ध्यान में रखा जाना चाहिए जब दो अधिनियम- एक ओर कारखाना अधिनियम और दूसरी ओर बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम/कल्याण उपकर

अधिनियम शामिल हों, जो दोनों कल्याणकारी कानून हैं। [पारस 27,32] [756- ए-बी]

इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक 2000 (2) एससीआर 1102:(2000) 4 एस. सी. सी. 406- पर निर्भर।

आत्मा राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पूर्णिया 1988 (2) पूरक एससीआर 528: (1988) 4 एस. सी. सी. 284; एमपी. खनिज उद्योग संघ बनाम क्षेत्रीय श्रम आयोग (मध्य) एटीआर 1960 एससी 1068: 1960 एस. सी. आर. 476; सुरेंद्र कुमार वर्मा बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण 1981 (1) एस. सी. आर. 789: (1980) 4 एस. सी. सी. 443; अमेरिकन एक्सप्रेस के कर्मचारी बनाम एंटेरिकन एक्सप्रेस का प्रबंधन (1985) 4 एस. सी. सी. 71; कैरू एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ 1976 (1) एससीआर 379: (1975) 2 एस. सी. सी. 791; बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां बनाम उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य (2009) 9 एस. सी. सी. 61; पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन पी. लिड बनाम मेसर्स हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड एंड एन. आर. 2016 (1) स्केल 1; ऋचा मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 2016 (1) एससीआर 316:(2016) 4 एस. सी. सी. 177; शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला 2015 एस. सी. आर. 70:(2016) 3 एस. सी. सी. 619- संदर्भित।

1.9 यह निवेदन कि कारखाना अधिनियम के तहत अनुमति देते समय, विभिन्न शर्तें लगाई जाती हैं जिन्हें अपीलकर्ताओं को पूरा करना आवश्यक है और ये शर्तें लगभग वही हैं जो बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में निहित हैं, स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। उक्त अधिनियम की खंड 6 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कारखाने अधिनियम के तहत पंजीकरण आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस खंड के तहत कारखानों की मंजूरी और पंजीकरण की आवश्यकता होती है, यहां तक कि प्रारंभिक

चरण में भी, यानी उस स्तर पर जब परिसर जहां कारखाना संचालित होना है, यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि वह कारखाने अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों आदि का ध्यान रखे। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण इस तरह से किया जाए कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के साथ- साथ कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कारखाने अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। यही कारण है कि इमारत पर कब्जा करने से पहले उसे पूरा करने के बाद भी, अधिभोगकर्ता द्वारा कारखानों के मुख्य निरीक्षक को खंड 7 के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण किया जा सके कि ऐसे सभी उपाय किए गए हैं या नहीं। इसलिए, जब कारखानों के निर्माण की अनुमति दी जाती है, तो उद्देश्य पूरी तरह से अलग होता है। [पैरा 33] [759- सी- एफ]

1.10 यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक कारण बताएँ नोटिसों में निहित उपकर की गणना पर आपत्ति का संबंध है, अपीलकर्ताओं के लिए निर्णय लेने वाले अधिकारियों के समक्ष आंदोलन करने का अधिकार होगा। [पैरा 35] [760- ए- बी]

पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य 1990 (3) एस. सी. आर. 111: (1990) 3 एससीसी 682; बी. एन. मुट्टो बनाम टी. के. नंदी 1979 (2) एस. सी. आर. 409: (1979) 1 एस. सी. सी. 361; श्री हरिप्रसाद शिवशंकर शुक्ला और एक अन्य बनाम श्री ए. डी. दिवेलकर और अन्य 1957 एस. सी. आर. 121; क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचुर बनाम रामानुज मैच इंडस्ट्रीज 1985 (2) एस. सी. आर. 119: (1985) 1 एस. सी. सी. 218; दादी जगन्नाधम बनाम जम्मुलु रामुलु और अन्य 2001 (2) पूरक एससीआर 60:(2001) 7 एस. सी. सी. 71; श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और एक अन्य 2001 (1) पूरक। एससीआर 115: (2001) 8 एस. सी. सी.

24; ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे 2002 (2) एस. सी. आर. 945:(2002) 4 एस. सी. सी. 297; दीपाल गिरीशभाई सोनी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ौदा 2004 एस. सी. आर. 212: (2004) 5 एस. सी. सी. 385; भिकुसा यामासा क्षत्रिय (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और एक अन्य 1964 एससीआर (1) 860; दीवान चंद बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम भारत संघ और अन्य 2011 (13) एससीआर 214:(2012) 1 एस. सी. सी. 101- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1990 (3) एस. सी. आर. 111 पैरा 10 को संदर्भित।

1979 (2) एस. सी. आर. 409 पैरा 10 में निर्दिष्ट।

1957 एस. सी. आर. 121 पैरा 10 को संदर्भित करता है।

1985 (2) एस. सी. आर. 119 पैरा 10 में संदर्भित है।

2001 (2) पूरक एस. सी. आर. 60 पैरा 10 में संदर्भित है।

2001 (1) पूरक एस. सी. आर. 115 पैरा 10 में संदर्भित है।

2002 (2) एस. सी. आर. 945 पैरा 10 को संदर्भित।

2004 एस. सी. आर. 212 पैरा 10 में निर्दिष्ट।

1964(1) एस. सी. आर. 860 पैरा 13 में निर्दिष्ट ।

2011 (13) एस. सी. आर. 214 पैरा 6 को संदर्भित करता है।

1980 (1) एस. सी. आर. 61 पैरा 25 को संदर्भित।

1988 (2) पूरक एस. सी. आर. 528 पैरा 27 में निर्दिष्ट।

1960 एस. सी. आर. 476 पैरा 28 में निर्दिष्ट।

1981 (1) एस. सी. आर. 789 पैरा 28 में निर्दिष्ट।

(1985) 4 एस. सी. सी. 71 पैरा 29 में संदर्भित है।

1976 (1) एस. सी. आर. 379 पैरा 30 में निर्दिष्ट है।

(2009) 9 एस. सी. सी. 61 पैरा 3 एल को संदर्भित करता है

2000 (2) एस. सी. आर. 1102 पैरा 32 पर निर्भर था।

2016 (1) स्केल 1 पैरा 32 को संदर्भित करता है।

2016 (1) एस. सी. आर. 316 पैरा 32 को संदर्भित।

2015 एस. सी. आर. 70 पैरा 32 में संदर्भित है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः दीवानी याचिका सं 6223/2016

के साथ

सिविल अपील संख्या 10187- 10188/2016

डब्ल्यू. पी. (ग) 2012 की सं. 64

डब्ल्यू. पी. (ग) 2013 की सं. 848

डब्ल्यू. पी. (ग) 2014 की सं. 385

2014 की दीवानी याचिका सं 6569

टी. पी. (ग) 2014 की सं. 342

टी. सी. (ग) 2015 की सं. 29

डब्ल्यू. पी. (ग) 2016 की सं. 174

डब्ल्यू. पी. (ग) 2016 की सं. 311

2014 की दीवानी याचिका सं 6571

टी. सी. (ग) 2016 की सं. 38

2016 दीवानी याचिका सं 10186

डब्ल्यू. पी. (ग) 2016 की सं. 698

2016 दीवानी याचिका सं 10189

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट कर सं. 772/2011 में न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांकित 28.04.2015 से।

सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., सी. ए. सुंदरम, गौरव बनर्जी, रवींद्र श्रीवास्तव, राणा मुखर्जी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अखिल सिब्बल, दीपक खुराना, सुश्री अदिति शर्मा, उमेश कुमार खेतान, अमर दवे, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री सदपूर्णा मुखर्जी, सत्येंद्र कुमार, ई. सी. अग्रवाल, विक्रांत पंचनंदा, महेश अग्रवाल, सुश्री नेहा नागपाल, शशांक मनीष, सुश्री वैदेही मिश्रा, साहिल टागोत्रा, बी. एस. बंथिया, प्रशांत शुक्ला, आलोक हुंका, नितिन गुप्ता, कुश अग्रवाल, निकिलेश रामचंद्रन, नीरज शेखर, अरुणाभ चौधरी, राहुल प्रताप, परशंतो चंद्र सेन, शिवांशु सिंह, उदयन वर्मा, सुश्री सना बत्ता, ए. वेनायगम बालन, टी. जी. नारायणन नायर, के. राघव चरयुलु, कैलाश पांडे, वैभव शुक्ला, रंजीत सिंह, सुश्री जे. कटारिया, के. वी. श्रीकुमार, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, राजीव दुबे, पुलकित तारे, श्रीकांत एन. फरदल, शिब सिंह, कुमार दुष्यंत सिंह, पुनीत तनेजा, मिश्रा सौरभ, अंकित कुमार। लाल, सुश्री अलका अग्रवाल, आर. आर. राजेश, ए. के. शर्मा, फ्रैंकलिन सीजर थॉमस, चांद कुरैशी, एम. पी. सिद्दीकी, उपेंद्र प्रसाद, नवीन चावला, टी. महिपाल, टी. ए. खान, राजेश रंजन, मुखेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता, उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए. के. सेकरी, जे. द्वारा दिया गया।

1. 2011 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 29105- 29106, 2016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 26363 और 2016 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 26330 में अवकाश अनुदत्त दी गई है। चूँकि कानून का शुद्ध प्रश्न शामिल है, हम स्थानांतरण याचिका और स्थानांतरण मामलों की अनुमति देते हैं और इन अपीलों के साथ, संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं को भी लेते हैं।

2. ये अपीलें अपीलार्थियों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की जाती हैं। हालाँकि, ये उच्च न्यायालय अपने दृष्टिकोण में सर्वसम्मत हैं और उसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। इन सभी मामलों में, अपीलकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों द्वारा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'कल्याण उपकर अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने उन नोटिसों को इस आधार पर उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी थी कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम या कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं थे क्योंकि वे कारखाने अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत थे। यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रासंगिक समय पर अपीलार्थियों द्वारा कोई विनिर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। वास्तव में, ये सभी अपीलार्थी सिविल कार्यों/कारखाने के भवनों आदि के निर्माण की प्रक्रिया में थे, जिसमें उन्होंने अपने कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई थी। चूंकि सिविल कार्यों के निर्माण की प्रक्रिया अपीलकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिसमें निर्माण श्रमिक लगे हुए थे, प्रतिवादी अधिकारियों ने यह विचार रखा कि उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधान जो निर्माण श्रमिकों के लिए थे, लागू हो गए और

अपीलकर्ताओं को उक्त श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर का भुगतान करना था। अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) जो 'भवन या अन्य निर्माण कार्य' को परिभाषित करती है, विशेष रूप से कहती है कि इसमें कोई भी भवन या निर्माण कार्य शामिल नहीं है जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 या खान अधिनियम, 1952 का प्रावधान लागू होता है। चूंकि अपीलार्थी कारखाने अधिनियम के तहत पंजीकृत थे, इसलिए वे अधिनियम की खंड 2 (डी) में निहित भवन या अन्य निर्माण कार्य की परिभाषा के दायरे में नहीं आते थे और इसलिए कहा गया कि अधिनियम उनकी खंड 1 (4) के आधार पर उन पर लागू नहीं होता था। सभी उच्च न्यायालयों ने अपीलकर्ताओं की उपरोक्त याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता किसी भी संचालन/विनिर्माण प्रक्रिया की अनुपस्थिति में में कारखाने अधिनियम की खंड 2 (एम) के तहत परिभाषित कारखाने की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे और इसलिए, केवल कारखाने अधिनियम की खंड 6 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होगा और उन्हें कल्याण उपकर अधिनियम के तहत उपकर का भुगतान करने के उनके दायित्व से बचाएगा। संक्षेप में, यह इन सभी अपीलों का विषय है। हालांकि, इसमें शामिल मुद्दे के पूर्ण निहितार्थ को समझने और उक्त मुद्दे का जवाब आदेश के लिए, कुछ तथ्यों पर ध्यान दें उचित होगा। इनमें से एक अपील से यह तथ्यात्मक प्रचार उन घटनाओं में उपयुक्त रूप से उपलब्ध है जो दीवानी याचिका सं 6223/2016 दाखिल करने के लिए हुई हैं।

3. इस अपील में, अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) द्वारा शुरू की गई टैरिफ- आधारित प्रतिस्पर्धी बोली में चुने जाने के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अनपारा में 2X600 मेगावाट क्षमता वाली कोयला- आधारित ताप विद्युत परियोजना "अनपरा सी" (परियोजना) स्थापित करने का

प्रस्ताव रखा। इस परियोजना में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दो स्टीम टर्बाइन जनरेटर (एसटीजी) और दो कोयले से चलने वाले भाप जनरेटर और संयंत्र का संतुलन शामिल है। अपीलकर्ता ने उपरोक्त परियोजना के संबंध में, कारखानों के निदेशक, उत्तर प्रदेश को एक आवेदन दिया, जिसमें प्रस्तावित संयंत्रों का खाका/चित्र प्रस्तुत किया गया और कारखाने अधिनियम, 1948 और उत्तर प्रदेश कारखाने नियम, 1950 के प्रावधानों के तहत परियोजना को कारखाने के रूप में पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया। अपीलकर्ता को एक कारखाने के रूप में उक्त परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश कारखाने नियम, 1950 के साथ पठित कारखाने अधिनियम, 1948 की खंड 6 के तहत पंजीकरण और लाइसेंस दिया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 ने उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) नियम, 2009 (संक्षेप में 'बी. ओ. सी. डब्ल्यू. नियम') को 04.02.2009 पर अधिसूचित किया। इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी सम तिथि का एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया था कि निर्माण गतिविधियों में लगे "प्रतिष्ठानों" को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. नियमों के प्रावधानों के तहत खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। साथ ही, जिला कलेक्टर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से सम तिथि का एक पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलकर्ता से बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. नियमों के प्रावधानों के तहत खुद को/अपने ठेकेदारों को पंजीकृत करने का आह्वान किया गया था। अपीलकर्ता ने अपने सम तिथि के पत्र के माध्यम से, जिला कलेक्टर, सोनभद्र के दिनांक 19.04.2010 के उपरोक्त संचार का जवाब देते हुए कहा कि अपीलकर्ता कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत परियोजना की निर्माण गतिविधि कर रहा था और इस तरह, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (1) (डी) को देखते हुए, परियोजना को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के आवेदन से छूट दी गई

थी, और इसके परिणामस्वरूप कल्याण उपकर अधिनियम और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. नियम परियोजना पर लागू होते हैं।

4. प्रतिवादी अपीलकर्ता द्वारा लिए गए उपरोक्त रुख से संतुष्ट नहीं थे। इस प्रकार, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करने में विफल रहने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, इस बारे में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांकित 17.02.2011 का कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सम तिथि का एक और नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता ने कल्याण उपकर अधिनियम की खंड 4 के तहत कल्याण उपकर नियमों के नियम 6 के साथ आवश्यक निर्माण गतिविधियों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। अपीलकर्ता द्वारा अनपारा में बस्ती के संबंध में की गई निर्माण गतिविधियों के संबंध में इसी तरह के कुछ और नोटिस जारी किए गए थे। जहाँ तक बस्ती का संबंध है, अपीलकर्ता ने कल्याण उपकर अधिनियम के तहत अपने प्रमुख ठेकेदारों द्वारा से खुद को पंजीकृत किया और उपकर का भुगतान करना शुरू कर दिया। हालांकि, निर्माण गतिविधि और कारखाने परिसर के संबंध में, अपीलकर्ता ने अपने रुख को दोहराया कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (1) (डी) के आधार पर, इसे इसके दायरे से बाहर रखा गया था। अपीलकर्ता के तर्क को प्रतिवादी द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके कारण उपकर की मांग करने के लिए और नोटिस जारी किए गए।

5. इस मोड़ पर, अपीलकर्ता ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 14.03.2011 और 02.04.2011 के नोटिसों की वैधता को चुनौती दी गईः निम्नलिखित आधारों पर उपकर के भुगतान की मांग करनाः

(i) कि अपीलकर्ता कल्याण उपकर अधिनियम के तहत दायित्व के आकलन के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि कारखाना अधिनियम परियोजना पर लागू होता है, और

परियोजना को बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (1) (डी) में निहित बहिष्करण कारण के आधार पर उक्त अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(ii) वह प्रत्यर्थी संख्या 2, दिनांक 02.04.2011 के आक्षेपित नोटिस के माध्यम से, परियोजना की लागत के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा देय कथित उपकर की गणना करने के लिए आगे बढ़ रहा था, न कि उक्त परियोजना के निर्माण की लागत के आधार पर, जबकि उपकर अधिनियम की योजना के तहत, उपकर केवल वार्षिक रूप से किए गए निर्माण की लागत पर देय है, न कि पूरी परियोजना लागत पर, जिसमें नागरिक निर्माण कार्यों के अलावा कई अन्य घटक शामिल हैं।

6. प्रतिवादी ने याचिका को चुनौती देते हुए अपना जवाबी शपथ पत्र दायर किया। सुनवाई के बाद, रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.04.2015 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है, जिसका सार पहले ही उपरोक्त पर ध्यान दें जा चुका है।

7. इनमें से कुछ अपीलों में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील श्री सुंदरम ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और निष्कर्ष पर सवाल उठाते हुए जोरदार प्रस्तुतियां दीं। अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी और श्री अखिल सिब्बल ने उन प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में अपना समर्थन दिया। इन प्रस्तुतियों को आगे मैसर्स प्रशांत शुक्ला, अरुणाभ चौधरी और के. राघव चरयुलु, अधिवक्ताओं द्वारा पूरक किया गया। इन वकीलों द्वारा की गई व्यक्तिगत दलीलों पर ध्यान दें आवश्यक नहीं हो सकता है। इसके बजाय, संक्षिप्तता के लिए, हम इन परामर्शों की प्रस्तुतियों को इसके बाद समेकित रूप में पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं।

8. इन वकीलों ने कल्याण उपकर अधिनियम के साथ पठित बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत उपकर के भुगतान के लिए प्रतिवादी द्वारा उठाई गई मांगों

पर दो तीखे हमलों का नेतृत्व किया है, जो निम्नानुसार हैः

i) पहली बार में, यह तर्क दिया जाता है कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम उन उपक्रमों पर लागू नहीं होता है जो कारखाने अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। इस प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (1) (डी) में निहित "भवन या अन्य निर्माण कार्य" की परिभाषा पर जोर दिया गया, जो निम्नानुसार हैः

> "धारा 2 (1) (घ): "भवन या अन्य निर्माण कार्य "से भवनों, सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई क्षेत्रों, सिंचाई, जल निकासी, तटबंध और नौवहन कार्यों, बाढ़ नियंत्रण कार्यों (तूफान जल निकासी कार्यों सहित), बिजली का उत्पादन, संचरण और वितरण, जल कार्य (पानी के वितरण के लिए चैनलों सहित), तेल और गैस प्रतिष्ठान, बिजली की लाइनें, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार बांध, नहरें, जलाशय, जलमार्ग, सुरंगें, पुल, वायडक्ट, एक्वाडक्ट, पाइपलाइन, टावर, कूलिंग टावर, ट्रांसमिशन टावर और ऐसे अन्य कार्यों का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस अभिप्रेत है जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए जाएं, लेकिन इसमें कोई भी कार्य शामिल नहीं है। (जोर दिया गया)"

(ii) दूसरा निवेदन, जो वास्तव में ऊपर उल्लिखित पहली प्रस्तुति से आता है, यह था कि मामले से निपटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानून के विपरीत था। इस ओर से, यह बताया गया कि उच्च न्यायालय ने यहां अपीलकर्ताओं के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि भले ही अपीलकर्ताओं ने कारखाने में काम करने के लिए पंजीकरण के लिए कारखाने अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किया था,

फिर भी अपीलकर्ताओं को कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधानों से बाहर नहीं रखा गया था क्योंकि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई विनिर्माण प्रक्रिया या कारखाने का संचालन शुरू नहीं किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ताओं ने कारखाने अधिनियम के अर्थ के भीतर 'कारखाने' के विवरण का जवाब नहीं दिया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, चूंकि अपीलकर्ताओं ने केवल परिसरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिन्हें अंततः कारखानों के रूप में उपयोग किया जाना है, और चूंकि ऐसी बिजली परियोजना शुरू नहीं हुई है और उत्पादन शुरू होने तक कारखाने अधिनियम के तहत कोई संचालन नहीं किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि "कारखाना" अस्तित्व में आ गया है और इसलिए, अपीलकर्ता कारखाने अधिनियम के तहत केवल पंजीकरण का लाभ उठाने के हकदार नहीं थे।

उपरोक्त दृष्टिकोण को गलत बताते हुए, अपीलकर्ताओं का यह तर्क था कि उच्च न्यायालय ने इस प्रासंगिक पहलू को नजरअंदाज कर दिया कि जब भवन निर्माणाधीन था, तब भी कारखाने अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की खंड 2 (डी) में निहित परिभाषा के आधार पर बाहर थे, जो भवन के निर्माण से संबंधित थी और इसलिए, विशेष रूप से निर्माण के चरण को ही शामिल करती थी। यह तर्क दिया गया कि मामले को उस कोण से देखा जाना चाहिए था। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए, यह भी प्रस्तुत किया गया कि विधानमंडल इस तथ्य के प्रति सचेत है कि कारखाना उस स्तर पर नहीं चल रहा है जब निर्माण या अन्य निर्माण कार्य चल रहा है। हालाँकि, इसने अभी भी उन इमारतों या अन्य निर्माण कार्यों को बाहर करने का विकल्प चुना है जिन पर कारखाने अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

9. उपरोक्त प्रस्तुतियों का विस्तार करते हुए, अपीलकर्ताओं ने बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) की परिभाषा को उस विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया कि एक बार कारखाने अधिनियम के प्रावधान लागू होने के बाद, बी. ओ.

सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के तहत श्रमिकों को स्वीकार्य सभी लाभ कारखाने अधिनियम के तहत भी दिए जाते हैं। इस प्रस्तुति को प्रावधानों की ओर इशारा करके पुष्ट किया गया था।

कारखाना अधिनियम के तहत अनुमति देते समय निर्धारित शर्तें। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता उन शर्तों के तहत जिन सुरक्षा उपायों और सुविधाओं के लिए बाध्य थे, वे बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में निर्धारित किए गए समान थे।

10. उपरोक्त जुड़वां प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों का समर्थन लेते हुए, अपीलार्थियों के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त प्रावधान में किसी भी अस्पष्टता की अनुपस्थिति में में खंड 2 (डी) को शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए और इस संबंध में निर्णयों की संख्या का हवाला दिया गया था। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैं:

i) पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड रिक्लेमेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ और अन्य 'में, इस न्यायालय ने' अर्थ 'शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि परिभाषा में' अर्थ 'शब्द का उपयोग किया गया है, तो इसमें कुछ चीजें या कार्य शामिल होंगे और परिभाषा में' अर्थ 'शब्द का उपयोग किया गया है, इसमें कुछ चीजें या कार्य शामिल होंगे और परिभाषा एक कठोर और तेज़ परिभाषा है और परिभाषा में दिए जाने के अलावा अभिव्यक्ति को कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कानून के शब्द अपने आप में सटीक और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके स्वाभाविक और सामान्य अर्थों में व्याख्या करने के अलावा और कुछ आवश्यक नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में केवल शब्द ही कानून के इरादे की सबसे अच्छी घोषणा करते हैं। यह न्यायालय बी. एन. मुट्टो बनाम 7- के में अपने फैसले का संदर्भ देने के बाद नंद?

उन्होंने कहा कि "न्यायालय को उपयोग किए गए शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए इरादे को निर्धारित करना होगा। यदि किसी अधिनियम के शब्द स्वयं सटीक और असंदिग्ध हैं, तो उन शब्दों को उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थों में व्याख्या करने से ज्यादा कुछ आवश्यक नहीं हो सकता है। यह आगे देखा गया कि अधिनियम के निर्माण का मुख्य नियम अधिनियमों को शाब्दिक रूप से पढ़ना है, यानी शब्दों को उनका सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ देना है।"

(ii) श्री हरिप्रसाद शिवशंकर शुक्ला और एक अन्य बनाम श्री ए. डी. दिवेलकर और अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अधिनियम स्वयं उपयोग किए गए शब्दों के लिए एक शब्दकोश प्रदान करता है, तो हमें क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या के लिए पहले उस शब्दकोश को देखना चाहिए। हम विधायिका के किसी भी अनुमानित इरादे से चिंतित नहीं हैं; हमारा काम क़ानून में व्यक्त इरादे को प्राप्त करना है।

iii) क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, त्रिचुर बनाम रामानुज मैच इंडस्ट्रीज में, अदालत ने कहा कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायी इरादे को लागू करने की दृष्टि से लाभकारी अधिनियमों का निर्माण उदार होना चाहिए, लेकिन जहां इस तरह के लाभकारी अधिनियम की अपनी कोई योजना है, वहां अदालत के लिए योजना से आगे बढ़ने का कोई वारंट नहीं है" और 'उन लोगों को वैधानिक लाभ देने के बहाने अधिनियम का दायरा बढ़ाएं जो योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

iv) दादी जगन्नाधम बनाम जम्मुलु रामुलु और अन्य में, इस न्यायालय ने विचार के लिए आने वाले प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित टिप्पणियां की:

"13..... व्याख्या के तय किए गए सिद्धांत यह हैं कि अदालत को इस

धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि विधायिका ने कोई गलती नहीं की और उसने वही किया जो वह करना चाहती थी। अदालत को, जहाँ तक संभव हो, एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को पूरा करेगा। निस्संदेह यदि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष या चूक है, तो अदालत सुधार या कमी को पूरा करने के लिए अपनी सहायता के लिए नहीं जाएगी। न्यायालय किसी अधिनियम में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता था या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता था जो वहां नहीं हैं, विशेष रूप से जब शाब्दिक पठन एक बोधगम्य परिणाम उत्पन्न करता है, न्यायालय किसी अधिनियम के विधानमंडल के दोषपूर्ण वाक्यांश की सहायता नहीं कर सकता है, या जोड़ और सुधार नहीं कर सकता है, और निर्माण द्वारा, कमियों को पूरा कर सकता है जो वहां हैं।"

v) श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में बताया कि किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कैसे की जाएः

"..... जब किसी अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द केवल एक अर्थ के लिए सक्षम हों। ऐसी स्थिति में, अदालतें परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करने में संकोच करती रही हैं। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द एक से अधिक अर्थों को जन्म देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, अदालतें निर्माण के ऐसे नियम को लागू करने से वंचित नहीं हैं। तीसरी स्थिति तब होती है जब इस तरह से माने गए अधिनियम के प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं होती है। यदि किसी अधिनियम का प्रावधान स्पष्ट,

असंदिग्ध है और किसी भी संदेह को जन्म नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में परोपकारी निर्माण का नियम लागू नहीं होता है।"

(vi) इसी तरह ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को निम्नानुसार समझायाः

"10. किसी भी अधिनियम में उपयोग किए गए किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति को अनावश्यक या अनावश्यक नहीं कहा जा सकता है। व्याख्या के मामलों में किसी को एक शब्द पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और दूसरे शब्दों पर बहुत कम ध्यान देना चाहिए। अधिनियम में किसी भी प्रावधान और किसी भी खंड में किसी भी शब्द को अलग से नहीं लिया जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान और प्रत्येक शब्द को सामान्य रूप से और उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक अधिनियम विधायिका का एक आदेश है। किसी अधिनियम पर विचार करते समय किसी भी शब्द की व्याख्या करने का प्राथमिक सिद्धांत विधायिका के पुरुष या संवेदनशील अधिनियम को इकट्ठा करना है। जहाँ शब्द स्पष्ट हैं और कोई अस्पष्टता नहीं है, और कोई अस्पष्टता नहीं है और विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, वहाँ न्यायालय के लिए वैधानिक प्रावधानों में संशोधन या परिवर्तन (एस. आई. सी.) करने का कार्य अपने ऊपर लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ भी भाषा स्पष्ट है, वहाँ विधायिका का इरादा उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है। ऐसा करते समय, अधिनियम में जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, उस पर भी ध्यान देना

होगा। उस निर्माण से बचना चाहिए जिसके लिए शब्दों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों की अस्वीकृति होती है। जैसा कि क्रॉफर्ड बनाम स्पूनर [(1846) 6 मूर पीसी 1 में प्रिवी काउंसिल द्वारा कहा गया हैः 4 एम. आई. ए. 179] "हम किसी अधिनियम के विधानमंडल के दोषपूर्ण वाक्यांशों की सहायता नहीं कर सकते हैं, हम जोड़ या सुधार नहीं कर सकते हैं और निर्माण द्वारा 'कमियों को जोड़ सकते हैं जो वहां बची हैं। एक साधारण शब्द के मामले में सामान्य अनुप्रयोग को प्रतिस्थापित करने या व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। ध्यान इस बात तक सीमित होना चाहिए कि विशेष मामले को तय करने के लिए क्या आवश्यक है। यह सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ पर्याप्त होगा। (देखिएः ग्वालियर रेयन्स सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यू. वी. जी.) कं. लिमिटेड बनाम निहित वनों के संरक्षक [1990 एस. सी. सी. 785: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1747], भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल (1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 323: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 248: (1992) 19 एटीसी 219: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 96] भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनामःकीमतःवाटरहाउस [(1997) 6 एस. सी. सी. 312] और हर्भजन सिंह बनाम भारतीय प्रेस परिषद [(2002) 3 एस. सी. सी. 722; जे. टी. (2002) 3 एस. सी. 21]"

vii) दीपाल गिरीशभाई सोनी और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बरेडा में, विचार के लिए आने वाले प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, सिद्धांत

को लाभकारी विधान के संदर्भ में भी लागू किया गया था, जब भाषा सरल थी, जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को दर्शाती थी, निम्नलिखित शब्दों में:

> "53. यद्यपि अधिनियम लाभकारी है और इस प्रकार, विधायी आशय को लागू करने की दृष्टि से उदार निर्माण का हकदार है, लेकिन यह सामान्य बात है कि जहां इस तरह के लाभकारी विधान की अपनी कोई योजना है और इसमें कोई अस्पष्टता या संदेह नहीं है, तो न्यायालय उससे आगे नहीं बढ़ेगा और उन लोगों को वैधानिक लाभ देने के बहाने अधिनियम का दायरा बढ़ाएगा जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। (क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. निगम देखें। बनाम रामानुज मैच इंडस्ट्रीज (1985) एस. सी. सी. 218: 1985 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 212: ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 278)।"

उपरोक्त सभी निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा हमें सुझाए गए तरीके से बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) की व्याख्या करते हुए इस शाब्दिक निर्माण का पालन करने का जोरदार आह्वान किया गया था।

11. श्री राणा और श्री श्रीवास्तव ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए समान रूप से स्वास्थ्यवर्धक प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रबल याचिका यह थी कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) के प्रावधानों की व्याख्या करते समय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से उचित था और अपीलार्थियों द्वारा सुझाई गई कोई भी अन्य व्याख्या इन अधिनियमों के उद्देश्य को विफल कर देगी। यह तर्क दिया गया कि कारखाना अधिनियम के तहत केवल पंजीकरण का कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि अधिनियम की खंड 2 (एम) में निहित 'कारखाना' की परिभाषा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब

वास्तव में विनिर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कारखाने अधिनियम के तहत 'श्रमिक' की परिभाषा में निर्माण श्रमिक शामिल नहीं हैं और इसलिए, निर्माण श्रमिक विभिन्न लाभों के हकदार नहीं होंगे जो कारखाने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में निहित हैं। यह इस कारण से भवन के निर्माण के चरण में है, जिसे अंततः एक कारखाने के रूप में उपयोग किया जाना है, के प्रावधान बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम लागू होगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, इसके पीछे "श्रेष्ठ उद्देश्य" को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस अधिनियम को जो कमजोर खंड, यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए है, उसे उस निर्माण को देकर उदारता से समझा जाना चाहिए जो उन्हें दूसरे दृष्टिकोण को छोड़कर लाभ प्रदान करता है जो उन्हें इससे वंचित करेगा। अधिनियमों के तहत लाभ प्राप्त करना, इस रंग में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायाधीशालय से इस मामले में पूर्ण न्यायाधीश करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को लागू करने का पुरजोर आग्रह किया, जो प्रचलन में है। यह भी तर्क दिया गया कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) में निहित बहिष्करण प्रावधान को कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

12. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर अपना उचित और गंभीरता से विचार किया है, जो इन दलीलों के योग्य हैं। केंद्रीय मुद्दा वह अर्थ है जो अधिनियम की खंड 2 (डी) की भाषा को सौंपा जाना है, विशेष रूप से वह भाग जो प्रकृति में बहिष्कृत है, यानी जिसमें ऐसे भवन और निर्माण कार्य शामिल नहीं हैं जिन पर कारखाने अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इस केंद्रीय मुद्दे की पकड़ में आने से पहले, हम उन उद्देश्यों का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिनके साथ कारखाने अधिनियम और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम लागू किए गए थे, क्योंकि यह ऊपर वर्णित मुख्य मुद्दे का उत्तर देने का मार्गदर्शक मार्ग होगा।

13. जहाँ तक कारखाना अधिनियम का संबंध है, इसकी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि यह कारखानों में श्रम को विनियमित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। यह मुख्य रूप से कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक और व्यावसायिक खतरों से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उस उद्देश्य के लिए यह मालिकों या कब्जाधारियों पर लापरवाह और लापरवाह श्रमिकों की रक्षा करने और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कुछ दायित्वों को लागू करना चाहता है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि श्रमिकों को स्वस्थ और स्वच्छ परिस्थितियों में काम करना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए यह प्रावधान है कि श्रमिकों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। कारखाना अधिनियम में आकस्मिक प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए हैं कि उद्देश्यों को पूरा किया जाए और राज्य सरकारों को प्रभावी पर्यवेक्षण बनाए रखने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करने, रिपोर्ट मंगाने और निर्धारित रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत नियोक्ता का कर्तव्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुरक्षित करना है और इसका विस्तार पर्याप्त संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, श्रमिकों पर पर्यवेक्षण, स्वस्थ और सुरक्षित परिसर, काम करने की उचित प्रणाली और उचित प्रतिबंध देने तक है। इसलिए, अधिनियम के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं जो कारखानों के मालिकों पर निरीक्षण कर्मचारियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य, स्वच्छता, भीड़भाड़ की रोकथाम और प्रकाश, पेयजल आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के लिए दायित्व लागू करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि काम के घंटों और युवाओं और महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध और मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी देना। भिकुसा यामासा क्षत्रिय (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ

और एक अन्य, इस न्यायालय ने इस अधिनियम को बनाने की आवश्यकता और तर्क पर प्रकाश डाला और उन उद्देश्यों पर प्रकाश डाला जिन्हें वह निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करना चाहता थाः

> "9. कारखाना अधिनियम, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, कारखानों में श्रम को विनियमित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। यह अधिनियम मुख्य रूप से कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक और व्यावसायिक खतरों से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उस उद्देश्य के लिए यह मालिकों या कब्जाधारियों पर लापरवाह श्रमिकों की रक्षा करने और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कुछ दायित्वों को लागू करना चाहता है। अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को स्वस्थ और स्वच्छ परिस्थितियों में काम करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए यह प्रावधान है कि श्रमिकों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आकस्मिक प्रावधान किए गए हैं कि उद्देश्यों को पूरा किया जाए और राज्य सरकारों को प्रभावी पर्यवेक्षण बनाए रखने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करने, रिपोर्ट मंगाने और निर्धारित रजिस्टरों का निरीक्षण करने का अधिकार है। नियोक्ता का कर्तव्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुरक्षित करना है और इसका विस्तार पर्याप्त संयंत्र, मशीनरी और उपकरण, श्रमिकों पर पर्यवेक्षण, स्वस्थ और सुरक्षित परिसर, काम करने की उचित प्रणाली और उचित निर्देश देने तक है। इसलिए अधिनियम के

विभिन्न अध्यायों में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं जो कारखानों के मालिकों के लिए निरीक्षण कर्मचारियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य, स्वच्छता, भीड़भाड़ की रोकथाम और प्रकाश, पेयजल आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान के लिए दायित्वों को लागू करते हैं। श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि काम के घंटों और युवाओं और महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध और मजदूरी के साथ वार्षिक छुट्टी देना। एक समय में विनिर्माण प्रक्रिया में रोजगार को नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध का विषय माना जाता था और राज्य नियोक्ता पर कोई शुल्क लगाने से संबंधित नहीं था। हालाँकि अब यह माना जाता है कि श्रम के शोषण को रोकने और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों पर जोर देने में राज्य की महत्वपूर्ण चिंता है। कारखाना अधिनियम निस्संदेह श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं पर कई प्रतिबंध लगाता है लेकिन औद्योगिक संबंधों पर आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करना अनुचित नहीं है और न ही माना जा सकता है।"

14. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम पर आते हुए, विधायी इरादे को दर्शाते हुए इसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया हैः

(1) यह अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 85 लाख श्रमिक भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक भारत में असंगठित श्रमिकों के सबसे असंख्य और कमजोर वर्गों में से एक हैं। भवन और अन्य निर्माण कार्यों की विशेषता श्रमिकों के जीवन और अंगों के लिए उनके अंतर्निहित जोखिम हैं।

इस कार्य की विशेषता इसकी आकस्मिक प्रकृति, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अस्थायी संबंध, अनिश्चित कार्य घंटे, बुनियादी सुविधाओं की कमी और कल्याणकारी सुविधाओं की अपर्याप्तता भी है। पर्याप्त वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति में में, दुर्घटनाओं की संख्या और प्रकृति के बारे में आवश्यक जानकारी भी सामने नहीं आ रही है। ऐसी जानकारी की अनुपस्थिति में में, जिम्मेदारी तय करना या कोई सुधारात्मक कार्रवाई करना मुश्किल है।

(2) हालांकि कुछ केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधान भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों पर लागू होते हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय कानून की आवश्यकता महसूस की गई है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी उपायों को शुरू करने के लिए कल्याण बोर्ड के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कार्यों पर नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाना आवश्यक माना गया था।

15. इस अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में ही, भवन आदि के निर्माण के दौरान नियोक्ताओं द्वारा की गई निर्माण लागत पर उपकर लगाना आवश्यक समझा गया था। इसके परिणामस्वरूप कल्याण उपकर अधिनियम पारित हुआ। वस्तुओं का कथन और इस अधिनियम के पीछे के कारण भवन के संसाधनों को बढ़ाने के लिए नियोक्ताओं द्वारा की गई निर्माण लागत पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करना था, और भवन और भवन निर्माण के तहत राज्य सरकारों द्वारा गठित अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अध्यादेश, 1995।

16. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की योजना इस न्यायालय द्वारा दीवान चंद

बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स बनाम भारत संघ और अन्य मामले में विचार के लिए सामने आई यह स्वीकार आदेशते हुए कि उक्त अधिनियम के पीछे महान उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित बुनियादी मानवीय गरिमा प्रदान आदेशने के लिए भवन और निर्माण श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित आदेशना है, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "10. इस प्रकार बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि इसका एकमात्र उद्देश्य भवन और निर्माण श्रमिकों का कल्याण है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित बुनियादी मानव गरिमा के साथ जीने के उनके संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार से सीधे संबंधित है। इसमें केंद्र और राज्य स्तरों पर अधिकारियों के एक नेटवर्क की परिकल्पना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याण बोर्डों का गठन करके और उन्हें बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियों के साथ हर भवन और निर्माण श्रमिक को कानून का लाभ उपलब्ध कराया जाए। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के कल्याणकारी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने का साधन उपकर अधिनियम द्वारा से है, जिस पर इन अपीलों में असंवैधानिक के रूप में सवाल उठाया गया है।
>
> XXX XX XX"

17. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम, उपकर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की व्यापक योजनाओं से यह स्पष्ट है कि उनका एकमात्र उद्देश्य भवन और

अन्य निर्माण श्रमिकों, समाज में पारंपरिक रूप से शोषित वर्गों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करना और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना है। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और उपकर अधिनियम इस मामले में नया आधार बनाते हैं कि उपकर का भुगतान करने का दायित्व न केवल किसी भवन या प्रतिष्ठान के मालिक पर पड़ता है, बल्कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (1) (i) (iii) के तहत भी पड़ता है।

> "किसी ठेकेदार द्वारा या उसद्वारा से किए गए भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में, या किसी ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए भवन श्रमिकों के नियोजन के संबंध में, ठेकेदार"

ठेकेदार पर दायित्व का विस्तार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि किसी भी कारण से निर्माण पूरा होने के बाद किसी भी स्तर पर भवन के मालिक से उपकर एकत्र करना संभव नहीं है, तो इसे ठेकेदार से वसूल किया जा सकता है। उपकर अधिनियम और उपकर नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि उपकर उन ठेकेदारों के बिलों से स्रोत पर एकत्र किया जाता है जिन्हें मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है। संक्षेप में, उपकर का भार मालिक से ठेकेदार को दिया जाता है।" (जोर दिया गया)

17. संबंधित अधिनियमों के उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अब हम बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) के दायरे और दायरे पर विचार करते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों में से एक यह है कि उक्त प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या करने की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उन भवन या निर्माण कार्यों को बाहर करता है जिन पर कारखाना अधिनियम लागू होता है। इसी आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि कारखाने अधिनियम के तहत लाभ पहले से ही निर्माण कार्य में शामिल निर्माण श्रमिकों को दिया जाता है, इसलिए बी. ओ. सी.

डब्ल्यू. अधिनियम या कल्याण उपकर अधिनियम के तहत अपीलार्थियों के निर्माण या निर्माण कार्य में लगे निर्माण श्रमिकों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

18. शाब्दिक निर्माण पर आधारित तर्क से निपटने से पहले, हम दूसरे पहलू से निपटना चाहेंगे क्योंकि इसका उत्तर इस पहलू के उत्तर को भी सुविधाजनक बनाएगा। कारखाना अधिनियम की खंड 2 (एम) 'कारखाना' को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करती हैः

> "(एम) "कारखाना" से उसका परिसर सहित कोई भी परिसर अभिप्रेत है-
>
> (i) जिस पर दस या उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता से विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है, या सामान्य रूप से ऐसा किया जाता है, या
>
> (ii) जहां बीस या उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, या पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भी हिस्से में बिजली की सहायता के बिना एक निर्माण प्रक्रिया की जा रही है, या सामान्य रूप से इस तरह से किया जाता है, लेकिन इसमें [खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35)] या [संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित एक गतिशील इकाई, एक रेलवे चलने वाला शेड या एक होटल, रेस्तरां या खाने की जगह] के संचालन के अधीन एक खदान शामिल नहीं है।
>
> [स्पष्टीकरण [I]- इस खंड के प्रयोजनों के लिए श्रमिकों की संख्या की गणना करने के लिए एक दिन में [विभिन्न समूहों और

रिले] में सभी श्रमिकों को ध्यान में रखा जाएगा;]

[स्पष्टीकरण ॥- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल यह तथ्य कि एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट या एक कंप्यूटर यूनिट किसी भी परिसर या उसके हिस्से में स्थापित है, इसे कारखाना बनाने के लिए नहीं माना जाएगा यदि ऐसे परिसर या उसके हिस्से में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है।]"

19. कारखाना अधिनियम की खंड 2 (के) 'विनिर्माण प्रक्रिया' को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करती हैः

"विनिर्माण प्रक्रिया "का अर्थ है कोई भी प्रक्रिया -

(i) किसी वस्तु या पदार्थ को उसके उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान की दृष्टि से बनाना, बदलना, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, तेल लगाना, धोना, सफाई करना, तोड़ना, ध्वस्त करना या अन्यथा उपचार करना या अनुकूलित करना; या

(ii) [तेल, पानी, सीवेज या कोई अन्य पदार्थ पंप करना; या]

(iii) बिजली का उत्पादन, परिवर्तन या संचारण; या

(iv) मुद्रण के लिए रचना प्रकार, लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, लिथोग्राफी, फोटोग्राव्योर या अन्य सिमी जार प्रक्रिया या पुस्तक बाइंडिंग;] [या]

(v) जहाजों या जहाजों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परिष्करण या टूटना; [या]

(vi) [किसी भी वस्तु को शीत भंडारण में संरक्षित या संग्रहीत करनाः]

20. कारखाना अधिनियम की खंड 2 (1) में निहित 'श्रमिक' की परिभाषा पर

भी ध्यान दें आवश्यक है। यह नीचे लिखा हैः

(1) "कर्मचारी "से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया में, या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी या परिसर के किसी हिस्से की सफाई में, या विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया के विषय से संबंधित या उससे जुड़े किसी अन्य प्रकार के काम में, [प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी (ठेकेदार सहित) द्वारा या उसद्वारा से, प्रमुख नियोक्ता की जानकारी के साथ या उसके बिना, चाहे पारिश्रमिक के लिए हो या नहीं] कार्यरत है।

21. उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि "कारखाना" वह प्रतिष्ठान है जहां विनिर्माण प्रक्रिया बिजली की सहायता के साथ या उसके बिना की जाती है। इस प्रकार इस विनिर्माण प्रक्रिया या विनिर्माण गतिविधि को जारी रखना एक पूर्व शर्त है। यह ध्यान दें भी उतना ही उचित है कि इसमें केवल वे श्रमिक शामिल हैं जो उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जहाँ तक इन अपीलार्थियों का संबंध है, भवन का निर्माण उनकी व्यावसायिक गतिविधि या निर्माण प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में, भवन का निर्माण विशेष विनिर्माण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जो इनमें से अधिकांश अपीलों में बिजली का उत्पादन, संचरण और वितरण है। जाहिर है, जो श्रमिक भवन के निर्माण में लगे हुए हैं, वे भी कारखाने अधिनियम के तहत 'श्रमिक' की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। इन दोनों पहलुओं पर कोई दरार नहीं है और दोनों पक्ष उचित स्थिति में हैं। इसके बाद यह है कि ये निर्माण श्रमिक कारखाने अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आते हैं।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अपीलार्थियों द्वारा किए गए भवन के निर्माण में लगे निर्माण श्रमिक, जिनका अंततः कारखाने के रूप में उपयोग किया जाना है, बी. ओ. सी. डब्ल्यू.

अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के प्रावधानों से भी बाहर रहेंगे। क्या बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) में 'भवन और अन्य निर्माण कार्य' की परिभाषा प्रदान करते समय यह इरादा हो सकता है?इसका स्पष्ट उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

23. हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय का यह कहना सही है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ताओं ने कारखाने में काम करने के लिए पंजीकरण के लिए कारखाने अधिनियम की खंड 6 के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है, इसलिए इसका पालन नहीं होगा कि वे कारखाने अधिनियम के अर्थ के भीतर "कारखाने" के विवरण का उत्तर दें। हमने 'कारखाना' की परिभाषा को पुनः प्रस्तुत किया है और इसके एक खाली पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस चरण से पहले, जब परियोजना का निर्माण पूरा हो जाता है और निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कारखाना अधिनियम की खंड 2 (एम) के अर्थ के भीतर 'कारखाना' अस्तित्व में नहीं आता है ताकि उक्त अधिनियम के दायरे में आए।

24. अब हम बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) के निर्माण से संबंधित मुख्य मुद्दे का विज्ञापन करते हैं। अपीलार्थियों का तर्क है कि इसकी भाषा स्पष्ट है और विधायी आशय का पता लगाने के लिए इसका शाब्दिक निर्माण किया जाना चाहिए। हमारे विचार से, यह प्रस्तुत करने का कोई लाभ नहीं है बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम की खंड 2 (डी) जो भवन या निर्माण कार्य से संबंधित है, तीन भागों में है। पहले भाग में, विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उक्त अभिव्यक्ति में शामिल किया जाना है, अर्थात्, निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस। परिभाषा का दूसरा भाग उन इमारतों या कार्यों के लिए है जिनके संबंध में उपरोक्त गतिविधियाँ की जाती हैं। परिभाषा के तीसरे भाग में अपवर्जन खंड यह निर्धारित करते हुए शामिल है कि इसमें कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य शामिल नहीं है, जिस

पर कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63), या खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के प्रावधान लागू होते हैं, इस प्रकार, परिभाषा के पहले भाग में गतिविधि की प्रकृति शामिल है; दूसरे भाग में वह विषय वस्तु शामिल है जिसके संबंध में गतिविधि की जाती है और तीसरे भाग में वे भवन या अन्य निर्माण कार्य शामिल नहीं हैं जिन पर कारखाना अधिनियम या खान अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

25. यह विवाद में नहीं है कि अपीलआदेश्ताओं की परियोजनाओं का निर्माण "भवन या अन्य निर्माण कार्य" की परिभाषा द्वारा कवर किया गया है क्योंकि यह ऊपर बताई गई परिभाषा के पहले दो तत्वों को संतुष्ट आदेशता है, यह देखने के लिए कि क्या अपवर्जन खंड लागू होता है, हमें 'शब्दों की व्याख्या आदेश देने की आवश्यकता है लेकिन इसमें कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य शामिल नहीं है।

जिन पर कारखाना अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। सवाल यह है कि क्या कारखाना अधिनियम के प्रावधान अपीलार्थियों के भवन/परियोजना के निर्माण पर लागू होते हैं। हमारा दृढ़ मत है कि वे लागू नहीं होते हैं। कारखाना अधिनियम के प्रावधान केवल तभी "लागू" होंगे जब विनिर्माण प्रक्रिया शुरू होगी जिसके लिए भवन/परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और परियोजना के निर्माण की गतिविधि पर नहीं। इस प्रकार अपवर्जन खंड की व्याख्या की जानी चाहिए और यह उक्त खंड का स्पष्ट अर्थ होगा। हमारे द्वारा निर्दिष्ट अपवर्जन खंड का यह अर्थ ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण टायर और न्यायाधीश ए. पी. सेन द्वारा दो अलग- अलग, लेकिन सहमत राय दी गई थी, और हम दोनों राय के कुछ अंश यहां पुनः प्रस्तुत करते हैं:

"न्यायमूर्ति ए. पी. सेन (पैरा 23)

प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य पर अधिनियम के सामान्य उद्देश्य के आलोक

में विचार किया जाना चाहिए। 'अवधारणा या उद्देश्य से रहित' शब्दों की एक नंगी यांत्रिक व्याख्या अधिकांश कानून को निरर्थकता में बदल देगी। यह एक हितकारी नियम है, जो अच्छी तरह से स्थापित है, कि विधायिका के इरादे को समग्र रूप से अधिनियम को पढ़कर पाया जाना चाहिए।

न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर (पैरा 24!)

एक नीति- उन्मुख व्याख्या, जब कोई कल्याणकारी कानून निर्धारण के लिए आता है, विशेष रूप से एक विकासशील देश के संदर्भ में, सिद्धांत और पूर्ववर्ती द्वारा स्वीकृत किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 37 में निहित होता है क्योंकि न्यायिक शाखा, एक अर्थ में, राज्य का हिस्सा है। इसलिए 'नुकसान' को एक बड़ा, पूरा करने वाला अर्थ देना उचित है।"

26. परिभाषा के अपवर्जन खंड के लिए जिम्मेदार उपरोक्त अर्थ भी उस उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप है जिसे बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के अधिनियमन द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि अपीलकर्ताओं द्वारा सुझाए गए इस प्रावधान के निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो भवनों/परियोजनाओं के निर्माण में लगे निर्माण श्रमिकों को न तो कारखाना अधिनियम का लाभ मिलेगा और न ही बीओसीडब्ल्यू अधिनियम/कल्याण उपकर अधिनियम का। विधायिका की यह मंशा नहीं हो सकती थी। बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम निर्माण श्रमिकों को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून के टुकड़े हैं।

27. एक सामाजिक सुधार कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एक अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो। आत्म राम मित्तल बनाम ईश्वर सिंह पुनिया के मामले में निम्नलिखित अंश में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है।

"9, संसद या दूसरे शब्दों में, लोगों की इच्छा क्या है, यह पता लगाने में अक्सर न्यायिक समय और शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। ब्लैकस्टोन हमें बताता है कि विधायक की इच्छा की व्याख्या करने का सबसे उचित और सबसे तर्कसंगत तरीका उस समय उसके इरादों की खोज करना है जब कानून बनाया गया था, सबसे स्वाभाविक और संभावित संकेतों द्वारा। और ये संकेत या तो शब्द, संदर्भ, विषय वस्तु, प्रभाव और परिणाम, या कानून की भावना और कारण हैं। (अदालत द्वारा जोर दिया गया) इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां देखें (1765 के प्रथम संस्करण की प्रतिकृति, शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, 1979, खंड मैं,पृ. 59) मुखर्जी, जे. उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में पोपपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 274:1953 एससीआर 677:1953 क्रि एल. जे. 1105: (1953) 4 एस. टी. सी. 188] ने कहा कि प्रत्येक शब्द, वाक्यांश या वाक्य का अर्थ इसमें लगाया जाना था स्वयं अधिनियम के उद्देश्य का प्रकाश लेकिन बहुत पहले जज लर्नड हैंड ने कहा था कि शब्दों को उनके पीछे के उद्देश्य की कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि हम इरादे की तलाश से संबंधित हैं, लेकिन हम उन शब्दों के अर्थ की ओर देख रहे हैं जो विधायिका ने उपयोग किए हैं और कौन से शब्दों का सही अर्थ है। [एड.: उपरोक्त मामले में लॉर्ड रीड ने कहा थाः (ऑल ई. आर. पी. 814) "हम अक्सर कहते हैं कि हम संसद के इरादे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। हम उन शब्दों के अर्थ की तलाश कर रहे हैं जो संसद ने इस्तेमाल किए हैं। हम यह नहीं खोज रहे हैं कि संसद का क्या अर्थ

है, बल्कि उन्होंने जो कहा उसका सही अर्थ क्या है।"] जैसा कि ब्लैक-क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम में लॉर्ड रीड ने कहा था। पापियरवेर्के वाल्डोफ़- एशफ़ेनबर्ग ए. जी. [1975 ए. सी. 591,613: (1975) 1 सभी ईआर 810: (1975) 2 डब्ल्यूएलआर 513]। हमारा स्पष्ट मत है कि भाषा को ध्यान में रखते हुए हमें कानून के कारण और भावना को खोजना चाहिए।"

28. श्रम कानूनों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, यह इस न्यायालय द्वारा बार- बार कहा और दोहराया गया है। एम. पी. खनिज उद्योग संघ बनाम क्षेत्रीय श्रम आयोग (केंद्रीय), इस न्यायाधीशालय ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित रोजगारों में नियोजित श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करके सामाजिक न्यायाधीश करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है, और इसलिए उक्त प्रावधानों का अर्थ लगाने में अदालत को उसे अपनाना चाहिए जिसे कभी- कभी निर्माण के लाभकारी नियम के रूप में वर्णित किया जाता है। सुरेंद्र कुमार वर्मा बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण में, इस न्यायालय ने याद दिलाया कि 'रोटी और मक्खन' कानूनों की व्याख्या में शब्दार्थिक विलासिताएँ गलत हैं। कल्याणकारी कानूनों को, आवश्यक रूप से, एक व्यापक व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए। जहाँ कानून को कुछ प्रकार की शरारतों के खिलाफ राहत देने के लिए बनाया गया है, वहाँ न्यायालय को व्युत्पत्ति संबंधी भ्रमण करके घुसपैठ नहीं करनी है।

29. हम वर्कमेन ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बनाम मैनेजमेंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस के एक अंश को भी पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो शाब्दिक निर्माण के आधार पर अपीलार्थियों के तर्क का पूरा जवाब देता हैः

"4. वैधानिक निर्माण के सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। सामाजिक कल्याण कानून और मानवाधिकारों के कानून जैसे उदार महत्व के कानूनों में आने वाले शब्दों को प्रोक्रस्टियन बेड में नहीं रखा जाना चाहिए या लिलिपुटियन आयामों में संकुचित नहीं किया जाना चाहिए। इन कानूनों को लागू करने में शाब्दिक निर्माण के ढोंग से बचा जाना चाहिए और इसके दुरुपयोग की विलक्षणता को पहचाना जाना चाहिए और कम किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को ऐसे कानूनों के "रंग", "विषय- वस्तु" और "संदर्भ" के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए (हमने प्रेन्न बनाम साइमंड्स [(1971) 3 ऑल ईआर 237] में लॉर्ड विल्बरफोर्स की राय से शब्द उधार लिए हैं। इसी राय में लॉर्ड विल्बरफोर्स ने बताया कि कानून को शाब्दिक व्याख्या के किसी द्वीप में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि भाषा से परे पूछताछ करना है, तथ्यों के मैट्रिक्स से अलग होना चाहिए जिसमें वे सेट किए गए हैं; कानून की व्याख्या विशुद्ध रूप से आंतरिक भाषाई विचारों पर नहीं की जानी चाहिए।"

30. समान रूप से कैरू एंड कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ में निहित संदेश है।

"21. कानून "आकाश में सर्वशक्तिमान" नहीं है, बल्कि सामाजिक आदेश का एक व्यावहारिक साधन है। यह आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने वाली एक परिचालन कला है, और व्याख्यात्मक प्रयास को वैधानिक उद्देश्य से प्रेरित किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्याकरण अर्थ के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है लेकिन निर्देशित करने के लिए एक बुरा मास्टर है।"

31. बॉम्बे आनंद भवन रेस्तरां बनाम उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य में निम्नलिखित शब्दों में भावनाओं को प्रतिध्वनित किया गया थाः

> "20. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक लाभकारी कानून है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है, बीमारी, प्रसूति और रोजगार की चोट के मामले में कारखाने के कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करना और उसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान करना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा कानून है और एक सामाजिक कानून की व्याख्या करने के नियम कराधान कानून की व्याख्या के नियमों से अलग हैं। न्यायालयों को किसी भी ऐसे छल को स्वीकार नहीं आदेशना चाहिए जो सामाजिक विधान के प्रावधानों को विफल आदेश दे और न्यायालयों को, यदि आवश्यक हो, तो भी अधिनियम की भाषा पर दबाव डालना चाहिए ताकि उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके जो विधायिका ने इस विधान को अधिनियम की पुस्तक में रखने के लिए किया था। इसलिए, अधिनियम को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि इसके उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके।"

32. उपरोक्त दृष्टिकोण को लेते हुए, हम प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता से भी सहमत हैं कि बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम में निहित 'श्रेष्ठ उद्देश्य' को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब एक ओर कारखाना अधिनियम और दूसरी ओर बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम/कल्याण उपकर अधिनियम शामिल हों, जो दोनों कल्याणकारी कानून हैं, (इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक देखें, जिसका पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन पी. लिमिटेड बनाम में पालन किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002

और कंपनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ में मैसर्स हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड एंड अन्र.यहाँ बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में निहित उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार 'महसूस की गई आवश्यकता' की अवधारणा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस अधिनियम का उद्देश्य एक विशेष आवश्यकता यानी निर्माण गतिविधि में शामिल असंगठित श्रमिक वर्ग के कल्याण का ध्यान रखना है, जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता है और जिसे त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत भी आकर्षित होता है जिसे ऋचा मिश्रा बनाम, छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य और शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बटकृष्ण लुल्ला में इस न्यायालय के हाल के फैसलों में समझाया गया है।

33. हम अपीलार्थियों के इस तर्क पर विचार करने के लिए छोड़ दिए गए हैं कि कारखाना अधिनियम के तहत अनुमति देते समय, विभिन्न शर्तें लगाई जाती हैं जिन्हें अपीलार्थियों को पूरा करना आवश्यक है और ये शर्तें लगभग वही हैं जो बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम में निहित हैं। हम भी इस निवेदन से सहमत नहीं हैं। यह पहले से ही माना जाता है कि कारखाने अधिनियम के प्रावधान इन निर्माण श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं। उक्त अधिनियम की खंड 6 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कारखाने अधिनियम के तहत पंजीकरण आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस खंड के तहत कारखानों की मंजूरी और पंजीकरण की आवश्यकता होती है, यहां तक कि प्रारंभिक चरण में भी, यानी उस स्तर पर जब परिसर जहां कारखाना संचालित होना है, यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण इस तरह से किया जाएगा कि वह कारखाने अधिनियम में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों आदि का ध्यान रखे। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण इस तरह से किया जाए कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और खतरनाक प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के साथ- साथ कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कारखाने अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। यही कारण है कि

इमारत पर कब्जा करने से पहले उसे पूरा करने के बाद भी, अधिभोगकर्ता द्वारा कारखानों के मुख्य निरीक्षक को खंड 7 के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण किया जा सके कि ऐसे सभी उपाय किए गए हैं या नहीं। इसलिए, जब कारखानों के निर्माण की अनुमति दी जाती है, तो उद्देश्य पूरी तरह से अलग होता है।

34. यह दोहराने की कीमत पर कहा गया है कि निर्माण श्रमिक कारखाने अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए, बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम और कल्याण उपकर अधिनियम के तहत ऐसे श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों से इनकार नहीं किया जा सकता है।

35. इस प्रकार, हम मानते हैं कि ये सभी अपीलें किसी भी योग्यता से रहित हैं। तदनुसार, इन अपीलों के साथ- साथ इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं के साथ- साथ वे भी जो स्थानांतरण याचिका और स्थानांतरण मामलों का विषय हैं, लागत के साथ खारिज कर दिए जाते हैं। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक कारण दर्शाओ नोटिसों में निहित उपकर की गणना पर आपत्ति का संबंध है, अपीलार्थियों के लिए यह खुला रहेगा कि वे निर्णय करने वाले अधिकारियों के समक्ष आंदोलन करें।

36. कोई लागत नहीं।

निधि जैन

मामले खारिज कर दिए गए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।